न्यूट्रिलाइजेशन दे रहे हैं । जितना प्राइस में वृद्धि हुई है उसका 100 फीसदी न्यूट्रिलाइजेशन दे रहे हैं, पूरा कम्पनसेशन उनको मिलता है । . . . . **(व्यवधान)** . . . .39 उसमें लिखा है, उसको राउंड अप कर दिया है ज्यादा आता है तो उसको बढ़ा देते हैं । उसको राउंड अप करके रखा है । टैक्नीकली राउंड अप किये बिना केलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं ।

Mr. Desai I do not think you have got any point.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): We are fully satisfied.

Appropriation (No. 3) Bill, 1989.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1987, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill arises out of the demand for excess grants relating to the year 1986-87. Those excess demands were presented in pursuance of the recommendations o fthe Public Accounts Committee, 8th Lok Sabha, in their 147th report. The Committee have recommended regularization of the excess expenditure under article 115(1)(b) of the Constitution and the Lok Sabha has already voted the excess demands on the 10th May 1989. The details of the excess demands are available with the document already circulated to the hon. Members. Sir, I move.

The question was proposed.

श्री धूलेश्वर मीणा (राजस्थान) : विदाऊट डिसकशन पास कर दिया जाए ।

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : बिना डिसकशन पास कर दिया जाए ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार जो है दीवालिया हो गई है इसलिए बोलना जरूरी है । मान्यवर, 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संसद् द्वारा स्वीकृति धनराशि से 242 करोड़, 23 लाख, 26 हजार, 886 रुपये सरकार द्वारा जो व्यय किए गए हैं इसकी स्वीकृति माननीय वित्त मंत्री जी संसद् से लेकर भारत की संचित निधि से यह धन निकालना चाहते हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

महोदय, यह बहुत पहले का व्यय है और सम्भवतः यह व्यय हो भी चुका है । इसलिए इस अवसर पर इसके संबंध में कुछ कहना या इसमें कटौती का कोई प्रस्ताव पेश करना उचित नहीं प्रतीत होता लेकिन माननीय पाध्यक्ष जी यह सरकार हमेशा घाटे उा खर्च का ब्यौरा और बजट प्रस्तुत करती है और आज तक इस देश की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है थ। माननीय वित्त मंत्री जी अपने जबाव में कहेंगे कि 42 साल की बात सत कहिये लेकिन इस देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है इसका वर्णन करना या इसके बारे में इस सदन में विचार करना आवश्यक है। माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि 42 वर्षों की आजादी के बाद आज भी हम कर्ज में हैं । आज भी सरकार को विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है । आज जब हम संसद् में विनियोग विधेयक पर विचार कर रहे हैं सरकार के ऊपर बाहरी देशों का 55 हजार

[श्री ईश दत्त यादव]

करोड़ रुपये का कर्ज है और आंतरिक कर्ज 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये है। सरकार का 17 हजार करोड़ रुपया उधार का या बकाया है। यह हमारी सरकार की आर्थिक अवस्था है। आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस देश में 37 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। यह सरकार गरीबों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिए काम नहीं कर रही है। पिछड़े वर्गों के लिए दो आयोग बैठे। एक काका कालेलकर आयोग और दूसरा मंडल आयोग। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दी और मंडल आयोग की सिफारिशों का भी सरकार लागू करने में हीला-हवाली कर रही है। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। ये पिछड़े वर्ग, हरिजनों, गरीबों और आदिवासियों के उत्थान की बात सरकार जरूर करती है। सरकार हमेशा तो यह बात करती है पर पंचवर्षीय योजना के पन्नों पर बात करती है। हमेशा विदेशों से कर्जा लिया जाता है। माननीय मंत्री जी की बातें मैंने सुनी, ये संस्कृत के ज्ञानकार लगते हैं **(व्यवधान)** मैं इससे निवेदन करता हूं कि आज की सरकार चार्वाक के सिद्धांत पर चलती है "यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत", विदेशों से कर्ज लीजिए और इसका दुरुपयोग कीजिए। यह आज की सरकार की नीति है और आज की सरकार का सारा का सारा कार्यक्रम कुछ इसी तरह का चलता रहता है। अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय राज्य कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई भत्ते के संबंध में, यह स्वागत योग्य है। हर्ष की बात है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि डी-जब मंहगाई भत्ते की या वेतन वृद्धि की घोषणा होती है तो बाजार भाव भी बढ़ जाता है। अगर वेतन वृद्धि और मंहगाई भत्ते की घोषणा न भी होती तो भी इस वर्ष तो कमर मंहगाई बढ़ती चली जा रही थी वह कमर तोड़ हो गयी है। आज आदमी के जीवन की उपयोगी वस्तुएं, खाने का सामान, कपड़ा, दवाएं सब महंगी हो गयी हैं। मैं आज के वातावरण में माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार मंहगाई पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास कर रही है और मुझे तो ऐसा आभास होता है कि सरकार की पूंजीपतियों से बहुत अच्छी सांठगांठ है। पूंजीपतियों के कारखाने में जो भी माल, सामान तैयार हो रहा है उनके दाम बढ़ाने के लिए सरकार की पूरी सहमति रहती है और किसान जो मेहनत करके अन्न उत्पादित करता है, उसके खेत में पैदा किए हुए अनाज का समर्थन मूल्य सरकार पहले तो निर्धारित नहीं करती, अगर करती है तो कम करती है। केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): उदाहरण देकर समाप्त कीजिए। आपको सिर्फ 25 मिनट का टाइम है।

श्री ईश दत्त यादव: समाप्त कर रहा हूं बस दो-तीन मिनट और टाइम दे दीजिए।

मैं कह रहा था कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है कानपुर में और सरकार का विश्वविद्यालय है, यहां के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में पिछले वर्ष तो लागत 246.70 रुपये थी लेकिन इस वर्ष कहा कि 251.50 रुपये व्यय पड़ रहा है लेकिन सरकार किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 183 रुपये दे रही है। यह सरकार, मेरा आरोप है कि किसानों को हितैषी नहीं है और चाहकर, जब तक वे फसल उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को हितैषी का नहीं सुविधाएं उसके देश की हालत सुधरने वाली नहीं है, आर्थिक स्थिति आज की खराब होती चली जा रही है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जानते होंगे कि 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी तो उस समय राष्ट्रीय आय में कृषि का सहयोग 64 प्रतिशत था और आज 24 प्रतिशत रह गया है और आज यह हालत है कि इस

वर्ष भी और गत वर्ष भी आपको विदेश से गेहूं मंगाना पड़ा और अच्छा गेहूं नहीं मंगाया गया, सड़ा हुआ मंगाया था जो कि बहुत विवाद का विषय बना जब बन्दरगाह पर आया था । आपको विदेश से उर्वरक मंगाना पड़ रहा है ।

मान्यवर, आप समय नहीं देना चाहते हैं । मैं भी समय नहीं लेना चाहता हूं । केवल माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप भारत की संचित निधि से इस तरह से धन निकालकर व्यय कीजिए कि इसका लाभ गांवों, गरीबों और किसानों तक पहुंचे और इस देश के आम आदमी को लाभ मिल सके । क्योंकि मैं केवल आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1989-90 का जो आपने बजट बनाया है, इसमें आपकी राजस्व प्राप्तियां 52,630 करोड़ रुपया है और योजनागत व्यय आपका 27,814 करोड़ है और गैर-योजनागत व्यय जो है वह 54,347 करोड़ है, जो नहीं होना चाहिए ।

योजनागत व्यय से गैर-योजना व्यय अधिक नहीं होना चाहिए और जो राजस्व प्राप्तियां हैं इनसे गैर-योजनागत व्यय को पूरा करके योजनागत व्यय का कुछ हिस्सा पूरा करना चाहिए । ऐसा यह नहीं कर पा रहे हैं । इसीलिए आपकी घाटे की अर्थव्यवस्था और कर्जे की अर्थ-व्यवस्था है ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं फिर निवेदन करूंगा और दोहरा रहा हूं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से कि गरीब आदमी और आम आदमी के फायदे की बात सोचिए और इस पैसे का सदुपयोग वहां तक करिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, this Appropriation Bill is for an amount which has already been spent. So there is nothing for us to say on it. When the General Budget was placed before the House the Minister painted a rosy picture, but we all had our doubts about it, because an eminent Indian economist says that our position is very weak, that we are in the debt trap. And that is proved by so many things. One is deficit financing. Then, debt repayment amount has reached 30 per cent. Foreign exchange position is precarious. And these things are not being taken into account. The Reserve Bank report, the Economic Survey of India, all these give not the rosy picture painted by the Minister but the opposite. The Government should ponder over this very seriously. As I am raising this point, I give you a parallel of the agricultural front. On radio, TV and in Government publications which were given out production for the year 1988 was shown as 171 million tonnes; similarly, it has been reported on radio, TV and through Government publications that there has been increase in wheat and edible oils, that so many items in so much quantity have been imported. But at the same time when there is the question of allocation, there have been cuts, drastic cuts. See what is happening. If what they claim is correct, how is it that they resort to cuts in the distribution? Yesterday our Kerala Food Minister came over here for obtaining our quota. But he has got a reduced quota. The quota has been reduced from 1,45,000 tonnes to 1,00,000 tonnes per month...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): For Maharashtra also I have made a complaint.

SHRI P. K. KUNJACHEN: Yes, for every State. Palm oil quota has been reduced from 600 tonnes per month to 200 tonnes per month. This is what is happening. On one hand you say production is increasing, it is at the maximum. On the other, reduction is the result. So, in actual practice the picture we have is contrary to what you claim. Especially when elections come, the Congress Party brings

[Shri P. K. Kunjachen]

forward so many slogans. Way back we know they brought so many slogans. Slogans like Rama Rajya, Avadi socialism, socialistic pattern of society, Gandhian socialism, etc. were coming. Just as the chameleon changes its colour according to the circumstances, these people also bring out different slogans according to the election time. Previously, the 20-Point Programme was there and then it was the new 20-Point Programme and then, as part of the 20-Point Programme, there was the NREP and there was the RLEGP. And, Sir, now it is the Jawahar Rozgar Yojana and the amount set apart for this is Rs. 2,100 crores. Out of this, the NREP and the RLEGP alone get Rs. 1,211 crores. But, in the Budget, only a provision of Rs. 500 crores has been made. The total of all these comes to Rs. 1,700 crores. This is the actual total. But the rest may be arranged through deficit financing. But nothing has been mentioed here as to how this huge amount of Rs. 2,100 crores under the Rajiv Gandhi plan is going to be obtained. But they say that this amount would be spent. But I would like to remind the Members that even Mr. Rajiv Gandhi had once said that for every six rupees spent, only one rupee has reached the beneficiary. They have said that one member from every family under the poverty line would be given employment up to fifty to a hundred days. How can it be done? If we assume that a family consists of five members, then six crores of people should be given employment. I have made some calculations. At the rate of twenty rupees per person, a sum of Rs. 12 crores will be needed for one day and if they have to give employment for fifty day, a sum of Rs. 600 crores will be needed and for employment for one hundred days, the amount needed will be Rs. 1,200 crores. You have made a provision of Rs. 2,100 crores. You are making use of this for propaganda. We do not take a negative attitude towards this. Our party's attitude to this is the same as its attitude towards planning. Even in regard to planning, we have made alternative suggestions. While we criticise the Plans, we also try to implement them. Similarly, with regard to this also, we have strong criticism. At the same time, we see to it that this is implemented and the benefit goes to the deserving person. But we will also tell the truth about it to the people.

What is the result of all this in Kerala? Under the NREP, Kerala is to get Rs. 36.70 crores and under the RLEGP, Rs. 25.8 crores and the total comes to Rs. 60.50 crores. This is due to Kerala. When the Jawahar Rozgar Yojana has come, the allotment to Kerala is Rs. 50 crores in all which means that we are losing ten crores. Kerala is losing about ten crores under the new scheme and yet you are going on propagating that you are going to give employment to one member in every family living below the poverty line. How can it be done? I would, therefore, like to request the Minister to take urgent steps to see that at least the amount under these two schemes for Kerala is not reduced. Actually, the Goernment might not have taken into account the poverty line and also unemployment...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That's all.

SHRI P. K. KUNJACHEN: I hope the Government will consider about this and take necessary steps.

With these words, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Mohd. Khaleelur Rahman. Last speaker.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मैंने भी कहना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You did not give name. Now time is over. You should have given the name earlier. (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : (आंध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमन सर, यह जो फाइनेंस मिनिस्टरी का एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 1989 लाया गया है, वह यह है कि 31 मार्च, 1987 तक जो भी चंद डिपार्टमेंट्स की तरफ से जाइद खर्च हुआ है, वह तो हो चुका है और अब हमारे पास ऐसी कोई मुताबादिल तजवीज नहीं है, सिवाइसके कि इसको पास करें, इसको मंजूर करें । यह कहा गया है कि आपने जो खर्च किया है, वह वाजिब खर्च है । मगर इस बिल में यह बताया गया है कि चंद डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जिन पर खर्च हुआ है, मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि डिपार्टमेंट आफ टूरिज्म है, एनर्जी है पब्लिक वर्कस है वाटर सप्लाई है और डिफेंस सर्विसेज-आर्मी, नेवी, एयर फोर्स डिपार्टमेंट हैं, इसमें कहा गया है कि जाइद खर्च हुआ है ।

मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट पर कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा खर्च होने के बाद भी हमारे यहां जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वह जिस किस्म का का होना चाहिए , उस किस का डवलपमेंट उसमें नहीं हो रहा है । मिसाल के तौर पर हम कश्मीर में यह देख रहे हैं कि वाकयतन कश्मीर और फिर रियासतें हुकूमत का जो बजट है, वह जो टूरिज्म में चाहते हैं, उस बजट से वहां पर उनकी आमदनी होती है और खुद हुकूमते-हिंद को भी काफी आमदनी हासिल हो सकती है, मगर जो पंजाब में गड़बड़ है और कश्मीर में जिस किस्म के कम्युनल राइट हो रहे हैं, उससे वहां का टूरिज्म काफी बुरी तरह से मुताअस्सिर हो रहा है । जरूरत इस बात की है कि वहां कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को डेवलप किया जाय ।

इसी तरह से मैं नार्थ-ईस्ट के ताल्लुक से कहता हूं । कहा जाता है कि मनिपुर, नार्थ-ईस्ट का जो इलाका है, उसका कश्मीर है । मगर वहां पर फारनर के जाने पर बैन किया गया है । जरूरत इस बात की है कि उस देश को उठाया जाय ताकि फारनर वहां पर जा सके और वहां के टूरिज्म का ज्यादा डेवलपमेंट हो सके । चुनांचे साऊथ में खुद हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में ऐसे मुकामात हैं, जिनको टूरिज्म सेंटर की हैसियत से डेवलप किया जा सकता है । मगर हम यह देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इन टूरिज्म को डवलप करने की तरफ कोई खास ख्याल नहीं कर रही है । मैं हुकूमते-हिंद से यह दरख्वास्त करूंगा कि पूरे मुल्क में जहां टूरिज्म के सटर हैं। वहां उन को डेवलप किया जाए । इससे एक तो हमको फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगी और दूसरी बात यह कि जो वहां की रियासतें हैं, उनको भी इस टूरिज्म से फायदा होगा ।

चूंकि मुझे वक्त बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैं कोशिश इस बात की कर रहा हूं कि मुख्तसरन तमाम पाइंट को टच करके चलूं । कहा गया है कि एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है, उसमें भी जाईद खर्च हुआ है । मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त रियासतें–आंध्र प्रदेश निहायत ही एक्यूट पावर शॉर्टेज से दो-चार है । फिर वहां जितने भी थर्मल पावर प्लांटस हैं, उसमें कोयले की सख्त जरूरत है, जबकि खुद हमारी रियासत आंध्र प्रदेश की सिंगरौनी कोलरीज ऐसी है, जहां से कोयले की बहुत दावार होती है, मगर इंतिहाई अफसोस की बात है कि सिंगरौनी से जो कोयला पैदा होता है, वह रियासतें आंध्र प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटस को देने के बजाय दूसरी रियासतों में काफी दूर फासले पर भेज दिया जाता है । इस तरह कोयले की जो आमदोरफ्त पर खर्च होता है, उसमें बहुत इखराजात हो जाती है । दूसरी बात यह है कि रियासते आंध्र प्रदेश में जितने थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट में कोयले की कमी की वजह से हमारी रियासत इस वक्त एक्यूट इलेक्ट्रिसिटी के बोहरान से दो-चार है । मैं हुकूमते हिंद से और खास तौर पर मिनिस्टर आफ एनर्जी से

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

दरख्वास्त करूंगा कि सिंगारिनी कालरी में कोयले की जो पैदावार होती है, वह सबसे पहले रियासते आंध्रप्रदेश के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को मुहैया की जाए। अगर कुछ सरप्लस बच जाय तो बाहर भेजी जाय। दूसरी बात...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अपोजीशन का समय पूरा हो चुका है। 25 मिनिट का टाइम है। कुल एक घंटे का टाइम है और 25 से 35 मिनिट हो चुके हैं।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान: एक-दो पाइंट्स कहकर समाप्त कर दूंगा।

खास तौर पर डिफेंस डिपार्टमेंट के ताल्लुक से भी कहा गया है और खास तौर पर एअर फोर्स के ताल्लुक से कहा गया है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि मुसलसल एअर फोर्स के एक्सीडेंट्स वगैरह सुनने में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें एक तो मैंटेनेंस की बहुत जरूरत है। दूसरे प्रापर ट्रेनिंग और तीसरी टाइमली ग्राउंडिंग आफ एअर क्राफ्ट्स वगैरह की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि एअर क्राफ्ट्स के एक्सीडेंट्स कम-से-कम हो सकें।

फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इलिटरेसी ने पूरे मुल्क को एक भयानक जाल में ले लिया है। जरूरत इस बात की है कि हम मुल्क से इलिटरेसी खत्म करें। चुनांचे आनेवाला साल 1990 ईसवी इंटरनेशनल लिटरेसी इयर यूनेस्को की तरफ से मनाया जा रहा है जिसे कि हमें एक नेशन की तरह से फलरिस्पोंसिबिलटी देनी चाहिए। लिटरेसी के लिए एक कैम्पेन चलाना चाहिए ताक हमारे मुल्क से इलिटरेसी खत्म हो सके।

मुझे आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक तो आप नाम नहीं देते हैं फिर जब बहस हो जाती है तो मेरे पास आते हैं। दूसरे जब समय दिया जाता है तो समय के हिसाब से नहीं चलते हैं। सिर्फ दो मिनट में खत्म करेंगे आप? दो मिनट से तीसरा मिनट में एलाउ नहीं करूंगा।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, ऐसा मत कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : दो मिनट से ज्यादा बोलेंगे तो कभी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूं। यह मेरी गलती जरूर थी कि मैंने नाम नहीं दिया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अब उसे छोड़िए, आप बोलिए। टाइम जाता है।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, एप्रोप्रिएशन बिल में कहा गया है कि कुछ विभागों का जो खर्चा हुआ है सो ठीक हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खास तौर से एनर्जी विभाग का जो नाम लिया गया है, वह बिल्कुल ही गलत है। एनर्जी विभाग हिंदुस्तान का जितना नुकसान कर रहा है, खासकर कोल इंडिया जितना नुकसान कर रहा है, जितनी लूट मचा रहा है, वहां सार्वजनिक संपत्ति का जितना नुकसान हो रहा है। मान्यवर, मैं आपको एक इत्तला करना चाहता हूं कि बी० सी० एल० और सी० सी० एल० बहुत महत्व की सबसिडी कंपनी है। कोल इंडिया का एक दफ्तर धनबाद में है और एक दफ्तर रांची में है। वहां प्रोडक्शन ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे 1 हजार टन जहां है, वहां

नापनेवाला जाता है तो कहता है कि यह 3 हजार टन है । इस तरह से ओवर प्रोडक्शन दिखाते हैं । जब नाप होती है तो शार्टेज होती है। पिछली 21 अप्रैल को बी० सी० सी० एल० के दफ्तर में आग लगा दी गयी । जब मैंने सवाल किया तो उसकी जांच-पड़ताल शुरु हुई और उस जांच पड़ताल का नतीजा नहीं निकला तब तक वह कर दिया गया । मैं सरकार से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि जांच की जाए और बी० सी० सी० एल० और बी०सी०सी० एल० के जो पदाधिकारी हैं जोकि सारी घपलेबाजी कर रहे हैं, उन पर जांच बिठायी जाए । और नेशनल कारपोरेशन भी, मान्यवर, देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है । अभी रूस से शटललैस लूम मंगाया गया और उसका दाम सवा तीन लाख प्रति लूम है । पांच करोड़ छब्बीस लाख रुपए का मंगाया गया । वह ठीक से काम नहीं करते हैं और जिस एजेंट के जरिए वह मंगाया गया था और जिसके जरिए वह सौदा तय हुआ था, उसको बाई-पास करके नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के चैयरमैन ने दूसरों को दे दिया और उसका जो कमीशन लिखित में तय था रूस की कंपनी के जरिए, जिसका नाम है "टैक्सको मैस एक्सपोर्ट", उस लिखित एजेंट का 15 प्रतिशत कमीशन खाने के लिए एजेंट को बदल दिया और मान्यवर, जो उसका चैयरमैन है वह सारा कमीशन खा गया । तो मैं चाहता हूं कि सरकार को उसकी जांच कराए और जो कमीशन खा रहा है यह चैयरमैन, एन० टी०सी० का, उसको बुक किया जाय और उस पर जांच बैठाई जाय कि यह घटिया लूम कैसे मंगाया, जबकि 1984-85 में चार लूम मंगाए गए और चार लूम की जांच हो रही थी, वह (... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अभी नहीं, बस ।। ... **(व्यवधान)** ...

श्री राम अवधेश सिंह : मैं बैठ रहा हूं । एक वाक्य और कहना चाहता हूं। .. **(व्यवधान)** ...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : देखिए, यही आपकी दिक्कत है । ... **(व्यवधान)** ...

श्री राम अवधेश सिंह : एक वाक्य कहना चाहता हूं । अब तक तो कह दिया होता । ... **(व्यवधान)** ...

श्री बी० के० गढवी : आसन ग्रहण करें । ... **(व्यवधान)** ...

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं चाह रहा हूं कि बिहार पर थोड़ी सी कृपा की जाए । बिहार में जो बैंक हैं, यह बैंक के मंत्री हैं, कि 6,100 करोड़ रुपया गरीब बिहार ने डिपाजिट किया बैंक में और उसको केवल 2300 करोड़ रुपया एडवांस दिया गया । मैं चाहता हूं कि बिहार का पैसा आप दूसरे राज्य में जाकर नहीं लगायें, बिहार में लगायें। यह मैं चाहता हूं ।

श्री बी० के० गढवी : मान्यवर, मैं भी सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत आभारी हूं । वैसे तो किसी भी मैम्बर ने इसके रेलिवेंट पे बात नहीं की, एक्सैस डिमान्ड के रेलिवेंस पे तो किसी ने भी बात नहीं की ... **(व्यवधान)** ...

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : हम आपके आभारी हैं कि आपने हिन्दी में रिप्लाई किया । .. **(व्यवधान)** ..

SHR P. K. KUNJACHEN: There is no financial discipline. That is what it shows.

श्री बी० के० गढवी : मगर फिर भी रिकार्ड के लिए मैं यह कहूंगा कि हम बजटिंग मानिटरिंग मैकेनिज्म जो है, उसको भी टाइप कर रहे हैं ताकि आइन्दा भविष्य में जांच हो सके, एक्सैस डिमान्ड के लिए हमको कम से कम हाउस के सामने आना पड़े । इस नतीजे से बड़े माहिर सदस्य ने भी बहुत उल्टी-सीधी बातें की एग्रीकल्चर की बातें कीं । 1951 में किसान सुखी था, आज उससे ज्यादा सुखी है । ऐसा अगर उनका

[श्री बी०के० गढवी]

मानना है तो मुझे बड़ी हैरानी है कि शायद वह देश के किसानों की हालत पूरी तरह से जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। हां एक बात जरुर है कि जमाने में, आज से कोई 7-8 साल पहले 1977-78 में, किसानो को अपने खेतों मे अपने हाथ से आग जरुर लगानी पड़ी, वह एक जमाना आया था। उसके बाद बहुत खुशहाल है किसान, प्रोडक्शन भी बढ़ा है और किसान का लीविंग स्टेंडर्ड भी बढ़ा है। हम देहातो में देखते हैं कि 1951 में किसानों की जो स्थिति थी, वह भी हमने देखी है, आपने भी देखी है, पूरे माननीय सदस्यों ने, सब ने देखी है और आज की जो स्थिति है, किसानों की जो माली हालत है, स्टैंडर्ड आफ लीविंग है, उनका जो खर्चा है, वह उपभोग करते हैं, जिन चीजों का, उसमें काफी परिवर्तन आया तो यह कहना बिलकुल उचित नहीं होगा कि किसानों की स्थिति में गिरावट आ रही है।

श्रीमन, हमारे एक केरल के सदस्य ने कहा और उन्होंने कैल्कुलेशन किया कि जवाहर रोजगार योजना से कितने हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे यहां इतनी हजार फेमिलीज होंगी जो बिलो पावर्टी लाइन होंगी। मुझे यह कहना है कि शायद हम यहां बैठकर हिन्दुस्तान की परिस्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जवाहर रोजगार योजना के तहत जिस फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं होगा, उसमें से एक को रोजगार मिलने वाला है। अब यह कहना कि सारी फैमिलीज बिलो पावर्टी लाइन हैं, उनमें कोई काम करने वाला नहीं है, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि उनकी आय कम हो, उनकी फैमिली का खर्चा बढ़ा हो, इसलिए ये बिलो पावर्टी लाइन हैं। लेकिन यह कहा कि सारी बिलो पावर्टी लाइन हैं, जितने हमारे कुटुम्ब हैं, फैमिलीज हैं उन सब का जरिया सिर्फ आर० एल० ई० जी० पी० है या एन० आर० ई० पी० है या जवाहर रोजगार योजना है, वह मानना कठिन है। आप देश की वास्तविकता से परिचित रहिए आप समझते नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मगर 2100 करोड रुपया जो प्रधान मंत्री ने इस योजना के लिए तय किया है, यह सबसे बड़ी रोजगार योजना है, बहुत क्रांतिकारी है और इसकी उमंग आपको नहीं दिखाई देती है। लेकिन हमको दीखती है और आप देहातों में जाइए, गरीब लोगों में जाइए तो उनको यह उमंग दिखाई देती है। उनको यह भी दीखता है कि जैसे अभी आपने कहा कि 6 में से 1 रुपया गरीब तक पहुंच पाता है, उनको लगता है कि पंचायती राज का जब नया ढांचा बनेगा तो वहां जो खाने वाले बिचोलिए हैं उन पर कंट्रोल आएगा, वह रोजगार योजना पर निगरानी रखेंगे, अपना काम खुद करेंगे और आप उनके खिलाफ कहते हैं कि पंचायती राज नहीं होना चाहिए। हम सब को मिलाकर ऐसा नमूनेदार नक्शा पेश करना चाहते हैं ताकि कम से कम लीकेज हो, कम से कम पिलफरेज हो और गरीब आदमी के लिए जो धन आवंटन किया जाता है उसका लाभ उस आदमी को मिलना चाहिए, इसलिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, नई दिशायें देना चाहते हैं, नया स्वास्थ्य उनमें भर देना चाहते हैं, देहात के लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर, वह आप समझ नहीं सकते हो।

हमारे यादव जी बिहार की बात करते हैं कि बिहार की हालत बहुत खराब है, बिहार में बहुत घपले हैं *

They are not capable of grappling with the problem. This is their difficulty. From that point of view, I am saying this.

*Not recorded.

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्. . .*

श्री बी० के० गदवी : बहुत समझदार हैं . . . (व्यवधान)

श्रीमन्, यह जो ग्रांट एक्सेस हैं, यह पी० ए० सी० ने स्क्रुटिनाइज की है। इसमें लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य होते हैं। उनको भी लगा कि एक एक्सेस एक्सपेंडीचर वाजिब था। इसलिए इसको रेगुलराइज करना चाहिए। इसलिए यह बिल हम हाउस के सामने लाए हैं।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): What was the excess expenditure? He must also be relevant to his point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think this has been looked into by the PAC. (Interruptions)

श्री ईश दत्त यादव : श्रीमन् केवल जानकारी के लिए एक स्पष्टीकरण चाहता था कि जवाहर रोजगार योजना में आपने कहा कि 50 दिन या 100 दिन काम मिलेगा . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इसके ऊपर कल बहस होने वाली है। मैं भी इसके ऊपर बोलने वाला हूं। यह बड़ा अच्छा सब्जैक्ट है। कल इस पर बहस होगी। आप कल अपनी बात कहिए।

Now I put the motion.

The question is:

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 1987, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up clause—by—clause consideration of the Bill.

Clause 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. K. GADHVI: I move: "That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

Representation of the People (Amendment) Bill, 1989

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Representation of the People (Amendment) Bill, 1989, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 1989."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 12th May, 1989.

*Not recorded.